

रक्षा बलों के बीच एकीकरण

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में **चीफ ऑफ डेफेंस स्टाफ (CDS)** ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तीनों रक्षा सेवाओं के बीच एकीकरण के लिये नौ कार्यक्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें रसद, खुफिया, सूचना प्रवाह, प्रशिक्षण, प्रशासन, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन और रखरखाव आदि शामिल हैं।

- 'थिएटरीकरण' (परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिये एक सामान्य कमांडर के तहत एक ही थिएटर में तीनों सेवाओं की इकाइयों को एकीकृत करना) की प्रक्रिया सशस्त्र बलों द्वारा किये गए पुनर्गठन प्रयास का हिस्सा है, जिसे रक्षा बलों के एकीकरण और **एकीकृत थिएटर कमांड** के निर्माण के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

तीनों रक्षा सेवाओं के बीच एकीकरण (Integration Among Three Defense Services):

- भारत में तीनों रक्षा सेवाओं के एकीकरण में **इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड (ITC)**, चीफ ऑफ डेफेंस स्टाफ का कार्यालय, साइबर एवं स्पेस कमांड की स्थापना, संसाधन साझाकरण एवं संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास सुनिश्चित करना शामिल है।
- **इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड:**
 - एकीकृत थिएटर कमांड में सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिये एक ही कमांड के अधीन तीनों सशस्त्र सेनाओं (थल सेना, वायुसेना और नौसेना) के एकीकृत कमांड की परिकल्पना की गई है।
 - इन बलों (थल सेना, वायुसेना और नौसेना) के कमांडर अपनी कर्तव्यताओं और एवं संसाधनों के साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे।
 - एकीकृत थिएटर कमांड किसी एक विशिष्ट सेवा के प्रति जवाबदेह नहीं होगा।
 - तीनों बलों का एकीकरण संसाधनों के दोहराव को कम करेगा। एक सेवा के तहत उपलब्ध संसाधन को अन्य सेवाओं में भी उपयोग किया जा सकेगा।
 - सेनाएँ एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठान की एकजुटता मज़बूत होगी।
 - **शेकतकर समिति** ने 3 एकीकृत थिएटर कमांड बनाने की सफ़ारिश की है- चीन सीमा के लिये उत्तरी कमांड, पाकिस्तान सीमा के लिये पश्चिमी कमांड और समुद्री भूमिका के लिये दक्षिणी कमांड।
- **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त कमांड:**
 - **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक संयुक्त कमांड** है।
 - यह भारतीय सशस्त्र बलों का पहला **त्रि-सेवा थिएटर कमांड** है, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है।
 - इसका गठन वर्ष 2001 में द्वीपों में सैन्य परसिपत्तियों की तेज़ी से तैनाती बढ़ाकर दक्षिण-पूर्व एशिया और मलक्का जलडमरूमध्य में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिये किया गया था।
- अन्य त्रि-सेवा कमांड, **स्ट्रैटेजिक फोर्सज़ कमांड (SFC)**, देश की परमाणु परसिपत्तियों की डिलीवरी और परिचालन नियंत्रण की देखभाल करता है।
- **वर्तमान स्थिति:**
 - भारतीय सशस्त्र बलों के पास **वर्तमान में 17 कमांड** हैं। थल सेना और वायुसेना की 7-7 कमांड हैं। नौसेना के पास 3 कमांड हैं।
 - प्रत्येक कमांड का नेतृत्व एक **3-स्टार रैंक का सैन्य अधिकारी** करता है।

A new approach to defence

Understanding the theaterisation of the Indian armed forces that will be a significant departure from the current arrangement – a change experts say is integral to fighting future wars. By Rahul Singh

WHAT IS THEATERISATION?

It is a concept that seeks to integrate the capabilities of the three services and optimally utilise their resources for future wars and operations. It refers to placing specific units of the army, the navy and the air force under a Theatre Commander. Such commands are expected to come under the operational control of an officer from any of the three services, depending on the function assigned to that command.

LACK OF CONSENSUS?

A lack of consensus on the military's theaterisation model emerged earlier this month during a key meeting of top government officials reviewing a draft cabinet note on the new joint structures. This led to the government setting up an expert committee last week for consultations and to remove differences before the reform plan is sent to the Cabinet Committee on Security for approval. The panel has members of the armed forces, defence ministry and other ministries (finance and home).

WHO HAS RESERVATIONS ABOUT THE CURRENT MODEL?

While the army and navy are in favour of theatre commands, the Air Force has concerns. Its concerns are over:

- Division of air assets
- Nomenclature and jurisdiction of commands
- Leadership of theatre commands
- Dilution of powers of chiefs

The expert committee is expected to hold more discussions to iron out the details of the theaterisation plan and bring all stakeholders, particularly the IAF, on board. Deliberations on the proposal are likely to take more time and previous timelines may need to be revised.

HOW MANY COMMANDS DO ARMED FORCES HAVE RIGHT NOW?

17 single-service commands are currently spread across the country's geography. These are divided as follows:

ARMY – 7 commands
AIR FORCE – 7 commands
NAVY – 3 commands

Creating theatres would involve merging existing commands. The Port Blair-based Andaman and Nicobar Command and Strategic Forces Command are the two tri-service commands. The ANC command will come under the proposed Maritime Theatre Command and SFC will be under National Security Council.

WHAT WILL THEATERISATION ENTAIL?

The current theaterisation model under consideration seeks to set up at least six new integrated commands.

THE FIRST PHASE INVOLVES CREATION OF:

Air Defence Command: This will control air defence resources of all three services and will be tasked with protecting military assets from airborne enemies.

HEADED BY: A top three-star Indian Air Force officer

BASED IN: Prayagraj

Maritime Theatre Command: This will be responsible for securing India from seaborne threats and will have army and air force elements under it.

HEADED BY: A top three-star Indian Navy officer

BASED IN: Karwar, Karnataka

Ultimately, India is expected to have three other integrated land commands to secure its western, northern and eastern fronts. The northern command will have the entire jurisdiction of J&K and Ladakh, and has been kept separate as it faces adversaries on LoC and LAC. Additionally, a logistics command is in the works to avoid duplication of efforts and resources.

WHO IS RESPONSIBLE FOR THEATERISATION?

India's first chief of defence staff (CDS) General Bipin Rawat has been given the mandate to steer the theaterisation drive.

EXPECTED BY: JANUARY, 2023

Rawat, who took charge as CDS on January 1, 2020, is expected to bring about the integration of the three services in a three-year timeframe.

'ONLY WAY AHEAD'

Despite IAF's reservations, experts stressed that theaterisation is the only way forward to fight future wars, particularly in an era where the nature of combat is changing. The three services cannot work in silos and air defence is integral to fighting future wars for the era of stand-alone aerial weapons like armed UAVs, rockets, missiles and swarm drones has dawned.

"No service should feel that they will have an upper hand or become subordinate to another service. Such thinking does not reflect sound national strategic thinking. We should all be mature enough to take India's long-term interests into account."

— LT GEN DR SHEKHAR (retd), who headed a committee that recommended the appointment of CDS & creation of theatre commands

COMMON CONCEPT IN BIG MILITARIES

Most leading militaries, including those of the United States, Russia, China, United Kingdom and France, function as per the theatre command concept with the idea of seamless integration among the land, sea and air forces for better coordination and response. The US military, the world's most powerful, has 11 combatant commands, each with a geographic or functional mission. Similarly, the Chinese People's Liberation Army has five theatre commands – eastern, southern, western, northern and central, with its western theatre handling the entire border with India. Pakistan has sought Beijing's help to reorganise its forces under the same concept.

HT

तीनों सेवाओं के बीच एकीकरण में हाल के विकास:

- CDS की नियुक्ति और **सैन्य मामलों के विभाग (DMA)** का निर्माण रक्षा बलों के एकीकरण और उन्नति की दृष्टि में महत्वपूर्ण कदम है।
 - विशेष रूप से सैन्य मामलों से संबंधित कार्य DMA के दायरे में आएंगे। पहले ये कार्य रक्षा विभाग (DoD) के अधीन थे।
- CDS: जैसा कि वर्ष 1999 में **कारगिल समीक्षा समिति** द्वारा सुझाया गया था, यह सरकार का एकल-बहु सैन्य सलाहकार है।
 - यह तीनों सेनाओं के कामकाज की देख-रेख और उनका समन्वय करता है।
 - **DMA के प्रमुख के रूप में CDS** को अंतर-सेवा खरीद नर्णियों को प्राथमिकता देने का अधिकार प्राप्त है।
 - **CDS का महत्त्व:**
 - **सशस्त्र बलों और सरकार के बीच तालमेल:** CDS रक्षा मंत्रालय की नौकरशाही और सशस्त्र सेवाओं के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देता है।
 - **संचालन में संयुक्तता:** पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) को नष्क्रिय कर दिया गया है क्योंकि CDS संचालन में अधिक संयुक्तता को बढ़ावा देता है।
- भारतीय वायुसेना (IAF) की चिंताएँ:
 - इस मॉडल के संबंध में सेना और नौसेना द्वारा थिएटर कमांड का समर्थन करने के बावजूद IAF को अपनी **हवाई संपत्तियों के विभाजन, कमांड के नामकरण, थिएटर कमांड के नेतृत्व एवं प्रमुखों की शक्तियों के कम होने को लेकर चिंता है।**
- नई यूनिफार्म:
 - ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल रैंक के सभी अधिकारी एक ही रंग के बरेट, रैंक के सामान्य बैज, समान बेल्ट बकल एवं जूते पहनेंगे तथा कंधों पर लेन्यार्ड/डोरी को हटाने का प्रस्ताव है।
- हाल ही में लोकसभा में **अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023** पेश किया गया ताकि नामित सैन्य कमांडरों, चाहे वे किसी भी सेवा से संबंधित हों, को **सैनिकों का कार्यभार संभालने और अनुशासन लागू करने का अधिकार** दिया जा सके।

अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023:

- इस प्रणाली में पाँच संयुक्त सेवा कमांड- पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, समुद्री और वायु रक्षा के शामिल होने की संभावना है।
- केंद्र सरकार एक अंतर-सेवा संगठन का गठन कर सकती है, जिसमें एक संयुक्त सेवा कमांड शामिल हो सकता है।
- यह अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ/ऑफिसर-इन-कमांड को अनुशासन बनाए रखने एवं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी कर्मियों के कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करने में सशक्त बनाएगी।
- किसी अंतर-सेवा संगठन का कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड ऐसे अंतर-सेवा संगठन का प्रमुख होगा।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/integration-among-defence-forces>

